VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(05 March 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- यूरोप को पुनः सशस्त्र करने की यूरोपीय संघ की "रीआर्म यूरोप" योजना
- भारतीय रेलवे के उपक्रम, IRCTC और IRFC को मिले 'नवरत्न' दर्जे का मतलब
- महाकुंभ 2025 में 'मियावाकी' वनारोपण पद्धति का उपयोग
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

यूरोप को पुनः सशस्त्र करने की यूरोपीय संघ की "रीआर्म यूरोप" योजना:

चर्चा में क्यों है?

- यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने 4 मार्च को यूरोप के रक्षा उद्योग को मजबूत करने और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक योजना पेश की। अध्यक्ष वॉन ने कहा कि "हम पुनः शस्त्रीकरण के युग में हैं, और यूरोप अपने रक्षा खर्च को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए तैयार है"।
- यूरोपीय संघ के प्रमुख ने "रीआर्म यूरोप" नामक इस योजना में यूरोप की रक्षा के लिए 800 अरब यूरो जुटाने तथा अमेरिकी सहायता के निलंबन के बाद यूक्रेन को तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए पांच-भागीय योजना का अनावरण किया। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में पहली बार घोषित किए गए इस कदम से देशों को अपने पैसे खर्च करने के तरीके में अधिक लचीलापन मिलेगा।

'रीआर्म यूरोप' योजना क्या है?

- रीआर्म यूरोप योजना चुनौतीपूर्ण समय में यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भविष्य के लिए एक पांच सूत्री योजना है। यह योजना यूरोपीय संघ के स्थिरता और विकास संधि में राष्ट्रीय पलायन खंड को सक्रिय करके यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी।
- इस योजना का पहला भाग राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा में सार्वजनिक निधि के उपयोग को उन्मुक्त करना है। यूरोपीय आयोग जल्द ही "स्थिरता और विकास संधि" के राष्ट्रीय पलायन खंड को सक्रिय करने का प्रस्ताव देगा। यह सदस्य राज्यों को अत्यधिक घाटे की प्रक्रिया को ट्रिगर किए बिना अपने रक्षा व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि करने की अनुमति देगा। उदाहरण के लिए: यदि सदस्य राज्य अपने रक्षा खर्च को औसतन सकल घरेलू उत्पाद के 1.5% तक बढ़ाएंगे तो इससे चार वर्षों की अवधि में लगभग 650 अरब यूरो का राजकोषीय स्थान बन सकता है।
- दूसरा प्रस्ताव एक नया साधन होगा। यह रक्षा निवेश के लिए सदस्य राज्यों को 150 अरब यूरो का ऋण प्रदान करेगा। यह मूल रूप से "बेहतर खर्च करने और साथ-साथ खर्च करने" के बारे में है। यह सदस्य राज्यों को मांग को एकत्रित करने

और साथ-साथ खरीदने में मदद करेगा। संयुक्त खरीद का यह तरीका लागत को भी कम करेगा, विखंडन को कम करेगा, अंतर-संचालन को बढ़ाएगा और रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा। और यह यूक्रेन के लिए लाभकारी हो सकता है।

- तीसरा बिंदु यूरोपीय संघ के बजट की शक्ति का उपयोग करना है। इस क्षेत्र में हम अल्पावधि में बहुत कुछ कर सकते हैं ताकि रक्षा-संबंधी निवेशों के लिए अधिक धन निर्देशित किया जा सके।
- कार्रवाई के अंतिम दो क्षेत्रों का उद्देश्य बचत और निवेश संघ और यूरोपीय निवेश बैंक के माध्यम से निजी पूंजी जुटाना है।

यूरोप रक्षा खर्च को क्यों बढ़ावा दे रहा है?

- जर्मनी की निवर्तमान विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक ने वॉन डेर लेयेन की योजना को "एक महत्वपूर्ण पहला कदम" कहा। उन्होंने कहा कि “शक्ति के माध्यम से शांति के लिए अब दो चीजें आवश्यक हैं: यूक्रेन, जो यूरोप की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है, के लिए अतिरिक्त सैन्य और वित्तीय सहायता और यूरोपीय संघ की रक्षा को मजबूत करने के लिए एक रक्षा व्यय में क्वांटम छलांग।

- उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगातार यूरोपीय देशों और अन्य नाटो सहयोगियों से अपने रक्षा खर्च को वर्तमान नाटो लक्ष्य, जो कि प्रत्येक वर्ष उनके सकल घरेलू उत्पाद का 2% है, से ऊपर बढ़ाने के लिए कहा है।
- हालांकि कई यूरोपीय देशों ने इस लक्ष्य को भी पूरा करने के लिए संघर्ष किया है और राष्ट्रपति ट्रम्प के पसंदीदा 5% के करीब अपने खर्च को बढ़ाने के बारे में चिंता व्यक्त की है।
- हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने हाल के दिनों में चल रहे यूक्रेन संघर्ष पर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है - जिसमें पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ वाद-विवाद, साथ ही ऐसी रिपोर्टें शामिल हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोक दी है - ने यूरोप पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा दिया है।
- इस संदर्भ में वॉन डेर लेयेन ने ब्रुसेल्स में संवाददाताओं से कहा कि "हम सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक समय में रह रहे हैं। हम नाटो में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। यह यूरोप के लिए एक क्षण है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं"।

भारतीय रेलवे के उपक्रम, IRCTC और IRFC को मिले 'नवरत्न' दर्जे का मतलब:

परिचय:

- एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) के बीच प्रतिष्ठित 'नवरत्न' का दर्जा दिया है। इस उन्नयन से IRCTC और IRFC 'नवरत्न' मान्यता प्राप्त करने वाली 25वीं और 26वीं कंपनियां बन गई हैं, जो भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे के कुल 12 CPSE में से सभी सात सूचीबद्ध CPSE को अब नवरत्न का दर्जा प्राप्त है।

'नवरत्न' का दर्जा क्या होता है?

- भारत सरकार ने 1997 में केंद्रीय सार्वजनिक निगमों (CPSE) के लिए 'नवरत्न' योजना शुरू की थी, ताकि वैश्विक नेता बनने की यात्रा में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ

वाले CPSE की पहचान की जा सके और उन्हें सहायता दी जा सके। वहीं बड़े CPSE के लिए 19 मई, 2010 से 'महारत्न' योजना शुरू की गई थी।

- उल्लेखनीय है कि 'नवरत्न' का दर्जा उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSE) को दिया जाता है जो बेहतरीन वित्तीय और बाजार प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं। यह मान्यता उनकी स्वायत्तता और वित्तीय अधिकार को बढ़ाती है।
- इस दर्जे का एक प्रमुख लाभ यह है कि कंपनियां केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता के बिना किसी एक परियोजना में 1,000 करोड़ रुपये या अपनी कुल संपत्ति का 15 प्रतिशत तक निवेश कर सकती हैं।
- केंद्र सरकार सार्वजनिक निगमों को उनके वित्तीय प्रदर्शन और परिचालन क्षमताओं के आधार पर तीन श्रेणियों - महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न - में वर्गीकृत करता है।

किसी कंपनी को 'नवरत्न' का दर्जा कब और कैसे मिलता है?

- उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक निगमों को दिया गया 'नवरत्न' का दर्जा केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली 'रत्न' कंपनियों की दूसरी श्रेणी है, जिसे लाभप्रदता, निवल मूल्य, कमाई, अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन आदि मानदंडों के आधार पर 'महारत्न' और 'मिनीरत्न' के बीच रखा जाता है।

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- वित्त मंत्रालय का सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) किसी CPSE को 'नवरत्न' का दर्जा देने के लिए निम्नलिखित छह संकेतकों पर विचार करता है:

  (i) निवल लाभ का निवल संपत्ति से अनुपात,

  (ii) उत्पादन या सेवाओं की कुल लागत में जनशक्ति लागत का अनुपात,

  (iii) मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पहले लाभ का नियोजित पूंजी या नियोजित पूंजी पर रिटर्न से अनुपात,

  (iv) ब्याज और कर से पहले लाभ का टर्नओवर से अनुपात,

  (v) प्रति शेयर आय, और

  (vi) कंपनी का अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन।

- इन छह संकेतकों का भार 10 (प्रति शेयर आय के लिए) से लेकर 25 (शुद्ध लाभ और शुद्ध संपत्ति के अनुपात के लिए) तक है। यदि किसी CPSE का सभी छह संकेतकों के लिए समग्र स्कोर 60 या उससे अधिक है, और पिछले पांच वर्षों में से तीन में उसे उत्कृष्ट या बहुत अच्छा MOU रेटिंग प्राप्त हुई है, तो उसे नवरत्न का दर्जा दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

'नवरत्न' दर्जे के क्या लाभ हैं?

- 'नवरत्न' दर्जा प्राप्त सार्वजनिक निगम बिना किसी पूर्व सरकारी मंजूरी के किसी एक परियोजना में 1,000 करोड़ रुपये या अपनी कुल संपत्ति का 15 प्रतिशत तक निवेश कर सकती हैं। इससे वे ज्यादा वित्तीय रूप से स्वायत्त हो जाती हैं।
- ये कंपनियां संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां बना सकती हैं, और बिना सीधे सरकारी हस्तक्षेप के विलय या अधिग्रहण कर सकती हैं। ये कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वतंत्र व्यवसाय और निवेश निर्णय भी ले सकती हैं।
- ये कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रवेश कर पाएगीं। ये कंपनियां सख्त नौकरशाही बाधाओं के बिना रणनीतिक गठबंधन बना सकती हैं और वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकती हैं।
- नवरत्न कंपनियों को वित्तीय रूप से स्थिर माना जाता है, जो उन्हें ज़्यादा निवेशकों को आकर्षित करने और शेयरधारकों को बेहतर रिटर्न देने में मदद करता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

महाकुंभ 2025 में 'मियावाकी' वनारोपण पद्धति का उपयोग:

चर्चा में क्यों है?

- 45 दिवसीय महाकुंभ 2025 उत्सव 26 फरवरी को समाप्त हुआ, जिसमें प्रयागराज में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस आयोजन के लिए प्रयागराज में सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पहल के हिस्से के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 'मियावाकी' पद्धति का इस्तेमाल किया गया। संस्कृति मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रयागराज प्रशासन ने इस तकनीक के माध्यम से शहर भर में 56,000 वर्ग मीटर भूमि को कवर किया।
- उल्लेखनीय है कि इस पद्धति का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों में "ऑक्सीजन बैंक" बनाने और जंगलों को फिर से आबाद करने के लिए किया जाता है, जो जापान में उत्पन्न एक वनीकरण विधि। इस पद्धति का इस्तेमाल पहले मुंबई और चेन्नई और दुनिया भर में किया जा चुका है, लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी हुई है।

'मियावाकी' पद्धति या 'मियावाकी वन' क्या होता है?

- 'मियावाकी वन' का नाम एक जापानी वनस्पतिशास्त्री और पारितंत्र विज्ञानी डॉ अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित तकनीक के नाम पर रखा गया है, जिसके तहत

विभिन्न प्रजातियों के पौधे एक दूसरे के करीब लगाए जाते हैं, जो अंततः घने शहरी जंगल में विकसित हो जाते हैं।

- इस पद्धति को 1970 के दशक में विकसित किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य भूमि के एक छोटे से हिस्से के भीतर हरित आवरण को सघन करना था।
- इस विधि के प्रयोग से पौधों की वृद्धि दस गुना तेज होती है, जिसके फलस्वरूप विकसित वन तीस गुना अधिक सघन होता है।

मियावाकी वृक्षारोपण विधि:

- इस विधि में प्रत्येक वर्ग मीटर के भीतर दो से चार विभिन्न प्रकार के देशज या स्थानिक पेड़ लगाना शामिल है।
- इस पद्धति में उपयोग किए जाने वाले पौधे अधिकतर आत्मनिर्भर होते हैं और उन्हें खाद और पानी जैसे नियमित रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है।

मियावाकी विधि के लाभ:

- इसकी शुरुआत के बाद से, मियावाकी पद्धति का उपयोग मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में किया गया है क्योंकि यह सीमित स्थानों में कई पौधे उगाने की अनुमति देता है।
- देशज पेड़ों का घना, हरा आवरण उस क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जहाँ जंगल स्थापित किया गया है।

- एक और लाभ यह है कि पौधे शुरुआती अवधि के बाद ज्यादातर आत्मनिर्भर होते हैं और उन्हें खाद और पानी जैसी नियमित देखभाल की जरूरत नहीं होती है।
- पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से स्थानीय तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं और छाया प्रदान करते हैं। ध्यातव्य है कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते कांक्रीटीकरण और निर्माण गतिविधियों ने अक्सर बाहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रचलित तापमान में योगदान दिया है - जिसे "हीट आइलैंड" प्रभाव के रूप में जाना जाता है। मियावाकी वन इसका मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं।

मियावाकी विधि की कमियां:

- उल्लेखनीय है कि यह विधि वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव मनुष्यों पर तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि, इसमें कुछ कमियां भी हैं।
- सबसे पहले इसके लिए शुरुआत में ही काफी निवेश की आवश्यकता हो सकती है, और सीमित स्थान में पौधों के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए कुछ जनशक्ति की भी आवश्यकता होती है।
- प्राकृतिक संरक्षणवादियों ने यह भी चेतावनी दी है कि मियावाकी वनों को, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से कमी जैसी ग्रह को परेशान करने वाली

प्रणालीगत समस्याओं के लिए, एकमात्र समाधान के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

- साथ ही शहरों में भी, मौजूदा शहरी नियोजन विधियों, संसाधन उपयोग और अपशिष्ट निपटान को बदले बिना केवल मियावाकी वनों के रूप ,में "मिनी-वन" लगाने से सीमित लाभ होने की संभावना है।

MCQs

1. चर्चा में रहे "रीआर्म यूरोप" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. यह चुनौतीपूर्ण समय में यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भविष्य के लिए एक पांच सूत्री योजना है।
   2. इस योजना में यूरोप की रक्षा तथा यूक्रेन को तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए 800 अरब यूरो जुटाने योजना बनायी गयी है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   Ans:(c)

2. हाल ही में भारतीय रेलवे के दो उपक्रमों को प्रतिष्ठित 'नवरत्न' का दर्जा दिया है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को 'नवरत्न' का दर्जा प्रदान करने वाला 'सार्वजनिक उद्यम विभाग' निम्नलिखित किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

   (a) वित्त मंत्रालय

   (b) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

   (c) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

   (d) प्रधानमंत्री कार्यालय

   Ans:(a)

3. चर्चा में रहे 'मियावाकी पद्धति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस वन में विभिन्न देशज प्रजाति के पौधे एक दूसरे के करीब लगाए जाते हैं, जो अंततः घने शहरी जंगल में विकसित हो जाते हैं।

2. इस पद्धति में उपयोग किए जाने वाले पौधे अधिकतर आत्मनिर्भर होते हैं और उन्हें खाद और पानी जैसे नियमित रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)

4. हाल में चर्चा में रहे 'मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति के महत्व' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) इस पद्धति से विभिन्न विदेशी पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों को उगाना संभव होता है।

(b) इससे पर्यावरण और स्थानीय समुदाय दोनों को कई तरह के लाभ मिलते हैं।

(c) यह वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से होने वाली कमी को पूर्णतः पूरा किया जा सकता है।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

Ans:(b)

5. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को ‘नवरत्न’ दर्जा देने वाली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत सरकार ने 2010 में केंद्रीय सार्वजनिक निगमों के लिए ‘नवरत्न’ योजना शुरू की थी।

2. यह मान्यता सार्वजनिक निगमों के विनिवेश प्रक्रिया को आसान बनाती है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(d)